प्रकाशनार्थ

पटना स्वच्छ वायु कार्ययोजना के लिए प्रमाणीकरण एवं परामर्श कार्यशाला

पटना, 29 जनवरी। आद्री स्थित नीतिगत अनुसंधान विचारमंच पर्यावरण, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन केंद्र (सीईईसीसी) द्वारा आज होटल पनाश में पटना स्वच्छ वायु कार्ययोजना (पीसीएएपी) के लिए प्रमाणीकरण एवं परामर्श कार्याशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण ने मुख्य वक्तव्य दिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्ययोजना के क्रियान्वयन को अंतिम रूप देने के लिए शहर के उत्सर्जन इनवेंट्री सबंधी शोध परिणामों पर हितधारकों द्वारा परामर्श और उनका प्रमाणीकरण और नियंत्रण के चिन्हित उपायों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन था।

स्वागत भाषण में आद्री के सदस्य सचिव डॉ. शैबाल गुप्ता ने परियोजना की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए बताया कि पटना को दुनिया में पांचवां सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है और वायु प्रदूषण का सामाजिक जीवन, व्यवहार और यहां तक कि नागरिकों के खुशी सूचकांक पर प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव होता है।

सीईईसीसी के निदेशक डॉ. अबिनाश मोहंती ने संदर्भ तय करने के लिए संबोधित करते हुए पटना स्वच्छ वायु कार्ययोजना परियोजना की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने से 2030 तक 20 लाख बच्चों की असमय मृत्यु रुक सकती है और कानून में कमियों को दूर करके इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार घोष ने अपने वक्तव्य में मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव के गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने यह भी कहा कि अत्यंत प्रदूषित पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कारण बिहार भी वायु प्रदूषण की समस्या झेल रहा है और बताया कि स्वच्छ वायु कार्ययोजना में 'अच्छे पड़ोसियों' के होने की जरूरत को रेखांकित किया गया है।

सीस्टेप के डॉ. जय आसुंदी ने बताया कि यह अभ्यास काफी श्रमपूर्वक किया गया है जिसमें नियंत्रण संबंधी उपायों के लिए सभी संबंधित विभागों के प्रयास भी शामिल हैं।

अपर मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण ने मुख्य वक्तव्य के दौरान बताया कि बिहार देश के अन्य प्रमुख राधधानियों की तुलना में वायु प्रदूषण पर कदम उठाने में पिछड़ रहा है। उन्होंने विद्यालयों में पर्यावरण के पाठ्यक्रम में एक शैक्षिक टूलकिट होने की अनुशंसा की।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने विशेष वक्तव्य देते हुए कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में अंतर काफी चिंता की बात है।चूंकि परिवहन क्षेत्र वायु प्रदूषण में योगदाता है इसलिए वे इसमें कमी लाने के लिए सभी संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अर्बन एमीशन के डॉ. सरत गुट्टीकुंडा और सीस्टेप की डॉ. प्रतिमा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रमुख शोध परिणामों पर कार्यशाला में एक सत्र आयोजित किया गया।इसमें कहा गया कि स्वच्छ वायु कार्ययोजना के लिए 10 वर्षों तक क्रियान्वयन का व्यय 2,600 करोड़ रु. है और वायु प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के संबंध में इसके पूर्ण अनुपालन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत है।

कार्ययोजना के क्रियान्वयन पर अंतिम सत्र की अध्यक्षता आवास एवं नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने की। उन्होंने बताया कि लक्ष्य 2025 तक के लिए तय किए जाने चाहिए और हमलोंगों को उस पर जोर-शोर से काम करने की जरूरत है।

सत्र में विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ श्री ए.एस. हरिनाथ द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। उन्होंने रेखांकित किया कि विश्व बैंक पटना स्वच्छ वायु कार्ययोजना को सहयोग देने के लिए कृतसंकल्प है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य मशीनरी ने कार्ययोजना की पहल को पूरा सहयोग दिया है और उसे देश के लिए आदर्श योजना के बतौर संभव बना दिया है। सत्र का संचालन शक्ति सस्टेनेबल इनर्जी फाउंडेशन के कार्यक्रम प्रबंधन श्री सिद्धार्थ चटपल्लीवार ने किया।

(अबिनाश मोहंती)